come of Rs. one lakh during the course of the search and cash of Rs. 20,000 was seized from his residence.

(c) In view of reply to part (b) above, does not arise.

Evasion of Income-tax by FPS owners in Delhi/New Delhi

3519. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the dealers of essential commodities, especially the FPS owners in Delhi and New Delhi, namely Shri Lakshmi Narain of Navrang Colony, Delhi and Shri Suraj Bhan of Tri Nagar, Delhi are avoiding the payment of a large sum towards income-tax with the collusion of Income Tax Officials;

(b) if so, what are the details of the raids conducted in the recent past against such dealers and how much unaccounted assets/jewellery have been recovered from them; and

(c) if no raid has been conducted, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) It has been reported by the concerned Chief Commissioner of Income-tax that no case of tax evasion by FPS owners in Delhi and New Delhi namely Shri Lakshmi Narain of Navrang Colony, Delhi and Shri Suraj Bhan of Tri Nagar, Delhi has come to notice so far.

(b) No searches have been conducted in the cases of such dealers in the recent past.

(c) Income-tax searches are conducted only on the basis of the specific information regarding tax evasion available with the Income-tax authorities. In the absence of such information, no searches can be conducted.

स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं

3520. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी है और परियोजनाश: ये कितने समय से लंबित पड़ी हैं ;

(ख) इन्हें स्वीकृति मिलने में हुये विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक अनुमति मिल जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) पांच वृहद और दो मध्यम परियोजनायें नामश: गलवा आधुनिकोकरण, पिपलोआ लिफ्ट, सिद्धमुख, नोहर, माउंट आबू बहुउद्देशीय, गरारदा सिंचाई तथा सुवर्ली । एक वृहद परियोजना वर्ष 1983 में तथा दूसरी वर्ष 1986 में प्राप्त हुई थी, और शेष वर्ष 1988 में प्राप्त हुई थीं । पांच वृहद परियोजनाओं पर टिप्पणियां अनुपालना हेतु राज्य सरकार को भेज दी गयी थीं । दो वृहद परियोजनाओं की संशोधित रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई हैं ।

राजस्थान में रुग्ण औद्योगिक एककों को पुन: शुरू करना

3521. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत राजस्थान में पता लगाये गए रुग्ण औद्योगिक एककों का जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन एककों को पुन: शुरू करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?